हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर

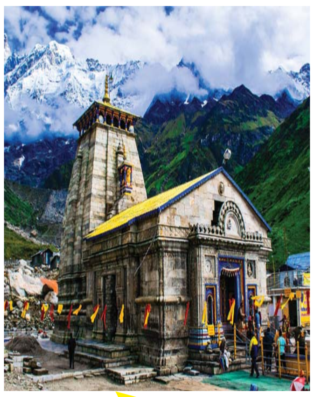

वर्ष:5 अंक:27 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये

pathpravah.com

हरिद्वार, रविवार, 01 फरवरी 2026

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल का किया शुभारंभ 326 करोड़ से अधिक की 61 योजनाओं की दी सौगात

पथ प्रवाह, कोटद्वार/पौड़ी गढ़वाल।

कोटद्वार में विकास और प्रकृति संरक्षण का अद्भुत संगम उस समय देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो दिवसीय बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोटद्वार एवं जनपद के विभिन्न विकासखंडों के लिए 326 करोड़ रुपये से अधिक की 61 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर क्षेत्र को बड़ी विकास सौगात दी। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जनसमूह, बर्ड वॉचर, छात्र-छात्राएं, युवा, महिलाएं और प्रकृति प्रेमी उपस्थित रहे। कोटद्वार पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सर्वप्रथम दिव्यांग बालक-बालिकाओं से मुलाकात कर उनसे आत्मीय संवाद किया और उनकी शिक्षा के संबंध में जानकारी ली। इसके उपरांत उन्होंने सिद्धबली मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद सनेह क्षेत्र में आयोजित बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम स्थल पर जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों का स्वागत किया। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज कोटद्वार की छात्राओं द्वारा गढ़वाली लोकभाषा में प्रस्तुत स्वागत गान ने कार्यक्रम को सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की, जबकि हेरिटेज स्कूल के नन्हे-मुन्ने बच्चों की पक्षी एवं प्रकृति संरक्षण पर आधारित प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। शनिवार को आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 21 विकास योजनाओं का शिलान्यास, जिनकी अनुमानित लागत 8,172.78 लाख रुपये, तथा 40 विकास योजनाओं का लोकार्पण, जिनकी लागत 24,439.55 लाख रुपये, किया गया। इस प्रकार कुल 32,612.33 लाख रुपये की विकास

योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने फेस्टिवल परिसर में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। पक्षियों की फोटो प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। उन्होंने पक्षी पहचान, संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रकृति संरक्षण के प्रति जनचेतना को मजबूत करते हैं। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा लगाए गए स्थानीय उत्पादों के स्टॉल की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि 21वां दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा और इसमें महिलाओं की भूमिका निर्णायक होगी।

मुख्यमंत्री ने कोटद्वार क्षेत्र में संचालित प्रमुख विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि बस टर्मिनल, आयुष चिकित्सालय, खोह नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु एसटीपी की स्थापना, मालन नदी पर 26 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुल निर्माण तथा कोटद्वार-नजीबाबाद फोरलेन सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास हेतु कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने हल्दूखाता में नगरीय पेयजल योजना की खनन प्रभावित जीर्ण-शीर्ण पाइपलाइन के सुदृढ़ीकरण, राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, पुस्तकालय, विज्ञान कक्ष, कंप्यूटर कक्ष एवं चहारदीवारी निर्माण, खोह नदी के दायें तट पर स्थित जीतपुर गांव में बाढ़ सुरक्षा कार्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झंडीचौड़ में 108 एम्बुलेंस सेवा तथा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में चहारदीवारी निर्माण की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक पक्षी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं और उनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड जैव विविधता की दृष्टि से देश के समृद्ध राज्यों में शामिल है, जहां लगभग 71 प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र से आच्छादित है। राज्य में प्रतिवर्ष लाखों प्रवासी पक्षी आते हैं तथा देश में पाई जाने वाली लगभग 1300 पक्षी प्रजातियों में से 400 से अधिक दुर्लभ प्रजातियां उत्तराखण्ड में पाई जाती हैं। सुरखाब पक्षी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह सुनहरे पंखों वाला दुर्लभ पक्षी राज्य की जैव विविधता की पहचान है। पक्षी पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, बीज प्रसार और पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाते हैं। विधानसभा अध्यक्षा एवं स्थानीय विधायक ऋतु खण्डूरी भूषण ने कहा कि उत्तराखण्ड में पाई जाने वाली लगभग 700 पक्षी प्रजातियों में से करीब 400 प्रजातियां कोटद्वार क्षेत्र में पाई जाती हैं। उन्होंने इस बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल को इको-टूरिज्म और बर्ड-टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताते हुए इसे राज्य सरकार के वार्षिक कैलेंडर में शामिल कर प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को 'बर्ड फेस्टिवल दिवस' के रूप में मनाने का सुझाव दिया।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने कहा कि यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि जैव विविधता, प्रकृति और जीवन के प्रति संवेदनशीलता का उत्सव है। उन्होंने कहा कि बर्ड फेस्टिवल वन्यजीव संरक्षण, इको-टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के क्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खोलता है और कोटद्वार को प्रकृति प्रेमियों की पहचान के रूप में स्थापित करेगा।

दो दिवसीय बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल के पहले दिन 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने सहभागिता की, जिनमें 300 छात्र-छात्राएं, 800 युवा, 400 महिलाएं, 100 बर्ड वॉचर और 900 से अधिक अन्य नागरिक शामिल रहे। फेस्टिवल के अंतर्गत आयोजित मैराथन दौड़, पेंटिंग, क्विज और निबंध प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को अंतिम दिन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

कार्यक्रम का संचालन पद्मेश बुड़ाकोटी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप सिंह रावत, उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पं. राजेन्द्र अणथ्वाल, उपाध्यक्ष सिंचाई समिति ऋषि कंडवाल, जिला पंचायत अध्यक्षा रचना बुटोला, मेयर नगर निगम कोटद्वार शैलेंद्र सिंह रावत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, डीएफओ लैंसडाउन जीवन मोहन दगाड़े, मंडी समिति अध्यक्ष सुमन कोटनाला, नगर आयुक्त पीएल शाह, उपजिलाधिकारी चतर सिंह चौहान, जिला पर्यटन विकास अधिकारी खुशाल सिंह नेगी, जिला अध्यक्ष भाजपा राज गौरव नौटियाल, पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, बर्ड वॉचर एवं आम नागरिक उपस्थित रहे।

सुनेत्रा पवार बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दिवंगत नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने शनिवार शाम यहां महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनी हैं।

पवार को आबकारी, खेल तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सौंपे गये हैं। ये विभाग उप मुख्यमंत्री रहते हुए अजित पवार के पास भी थे और इसके अलावा उनके पास वित्त एवं नियोजन विभाग भी थे। अब वित्त विभाग मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस ने अपने पास रखा है। पवार का 28 जनवरी को बारामती में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था।

श्रीमती पवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन में आयोजित संक्षिप्त समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी। शपथ ग्रहण समारोह में श्री फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, राकांपा के वरिष्ठ प्रफुल्ल पटेल समेत पार्टी के कई नेता तथा कार्यकर्ता और कुछ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

इससे पहले शनिवार दोपहर में श्रीमती पवार को राकांपा विधायक दल का नेता चुना गया था। उन्होंने नेता चुने जाने के बाद राज्यसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा भेज दिया। उन्हें छह माह के भीतर राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। माना जा रहा है कि वह श्री पवार के निधन से रिक्त हुई बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी।

श्रीमती पवार का जन्म महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में 18 अक्टूबर 1963 को एक किसान परिवार में हुआ।

भगवंतराव पाटिल और द्रौपदी बाजीराव पाटिल के घर पैदा हुई सुनेत्रा पवार ने औरंगाबाद में एसबी कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक की पढ़ाई की।

अरब देशों के साथ व्यापार, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग प्रगाढ बनाने को प्रतिबद्ध है भारत : मोदी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अरब देशों के साथ व्यापार और निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग को और प्रगाढ बनाने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है। श्री मोदी ने शनिवार को यहां अरब देशों के विदेश मंत्रियों, अरब लीग के महासचिव तथा अरब देशों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से मुलाकात की। ये सभी प्रतिनिधि भारत-अरब विदेश मंत्रियों की द्वितीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत यात्रा पर हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत और अरब जगत के लोगों के बीच गहरे और ऐतिहासिक

संबंधों को रेखांकित किया। इससे वर्षों से परस्पर रिश्तों और सुदृढ़ हुए हैं। प्रधानमंत्री ने आने वाले वर्षों के लिए भारत-अरब साझेदारी के बारे में अपना दृष्टिकोण साझा किया और व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहरायी ताकि दोनों पक्षों के लोगों को परस्पर लाभ मिल सके। श्री मोदी ने फिलिस्तीन के लोगों के प्रति भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया और ग़ाज़ा शांति योजना सहित शांति प्रयासों का स्वागत किया। उन्होंने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और संवाद को बढ़ावा देने में अरब लीग की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना भी की।

बजट में उत्तर बंगाल को क्षेत्रफल और आबादी से अधिक मिलेगा हक: अमित शाह

कोलकाता। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट के पेश होने से एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार उत्तर बंगाल को उसके क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात से अधिक बजट आवंटन देगी।

सिलीगुड़ी में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने उत्तर बंगाल के लोगों को आश्वस्त किया कि भविष्य में भाजपा सरकार बनने पर क्षेत्र के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा, 'मैं उत्तर बंगाल के लोगों से वादा करता हूं कि क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से जितना बजट बनता है, उससे कम से कम एक रुपया अधिक दिया जाएगा। उत्तर बंगाल के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा

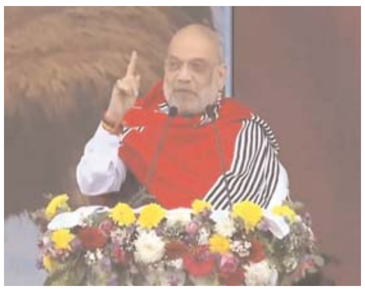

हमला बोलते हुए श्री शाह ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस उत्तर बंगाल को केवल राजस्व कमाने के साधन के रूप में देखती है। उन्होंने कहा, 'दीदी के लिए उत्तर बंगाल सिर्फ एक सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है। लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब विदाई का समय आ गया है। अप्रैल के अंत तक आपको जाना होगा,' कहते हुए उन्होंने राज्य में सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी की। बजट से ठीक पहले दिए गए श्री शाह के बयान को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि सिलीगुड़ी और पूरा उत्तर बंगाल लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ रहा है। पिछले तीन प्रमुख चुनावों- दो लोकसभा और एक विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस पर बढ़त बनाए रखी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर बंगाल की आठ में से सात सीटें जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। हालांकि 2024 के आम चुनाव में यह संख्या घटकर छह रह गई और केंद्रीय मंत्री निशीथ अधिकारी भी टीएमसी से हार गए, फिर भी भाजपा का वोट आधार स्थिर और मजबूत बना हुआ है।

हरिद्वार में मास्टर प्लान और यूनिटी मॉल पर सरकार का फोकस, डॉ. आर. राजेश कुमार

पथ प्रवाह, हरिद्वार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सुनियोजित शहरी विकास, पारदर्शी आवास व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में शासन स्तर पर विकास प्राधिकरणों की नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि योजनाओं का लाभ आम जनता तक समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पहुँच सके। सचिव आवास विकास एवं राज्य सम्पत्ति उत्तराखण्ड, डॉ. आर. राजेश कुमार ने शुक्रवार को हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) के सभागार में समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने एचआरडीए द्वारा एकत्र किए गए राजस्व, एकल एवं गैर-एकल आवासीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली। सचिव ने निर्देश दिए कि आवासीय आवेदनों पर शासन स्तर से लगाई गई आपत्तियों का त्वरित निस्तारण कर उन्हें तत्काल शासन को प्रेषित किया जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना में गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर

समीक्षा के दौरान सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों में पूर्ण पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण नहीं, बल्कि नागरिकों को सुरक्षित और टिकाऊ आवास

उपलब्ध कराना है।

मास्टर प्लान, सौंदर्यकरण और थर्ड पार्टी ऑडिट पर फोकस

डॉ. आर. राजेश कुमार ने विगत वर्षों में किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए पार्किंग स्थलों, सड़क किनारे सौंदर्यकरण, गमलों के रखरखाव और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। साथ ही मास्टर प्लान को प्राथमिकता बताते हुए कार्यों में कमियों की पुनरावृत्ति रोकने और थर्ड पार्टी एजेंसी से गुणवत्ता जांच कराने पर जोर दिया।

यूनिटी मॉल का स्थलीय निरीक्षण, काम में तेजी के निर्देश

बैठक के बाद सचिव ने निर्माणाधीन यूनिटी मॉल का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यह प्रधानमंत्री की प्राथमिक परियोजना है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष फोकस है। वर्तमान में लगभग 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। भारत सरकार से प्राप्त किस्त जारी कर दी गई है, शेष एस्केलेशन प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कार्य में तेजी लाई जा सके।

‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ को मिलेगा नया मंच

एचआरडीए सचिव मनीष कुमार सिंह ने जानकारी दी कि ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ योजना के तहत हरिद्वार जनपद का चयन किया गया है।

यूनिटी मॉल में 54 शॉप और 3 मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, जहां देश के सभी राज्यों और उत्तराखंड के 13 जनपदों के स्थानीय उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।

डॉ. आर. राजेश कुमार का बयान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि शहरी विकास योजनाएं पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और जनहित के साथ लागू हों। एचआरडीए द्वारा किए जा रहे कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण, समयबद्ध क्रियान्वयन और जनआवश्यकताओं को प्राथमिकता देना आवश्यक है। यूनिटी मॉल जैसी परियोजनाएं न केवल स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय मंच देंगी, बल्कि रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देंगी। सभी विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मास्टर प्लान के अनुरूप कार्य करें और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।

महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति रहें जागरूक, कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारों की रखें जानकारी: डॉ ललित नारायण मिश्र

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजनान्तर्गत महिला अधिकारों एवं समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विषय पर ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रेक्षागृह में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि सचिव जिला विधिक प्राधिकरण/सीनियर सिविल जज सिमरनजीत कौर ने दीप प्रज्वलित कर किया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए सचिव जिला विधिक प्राधिकरण/सीनियर सिविल जज सिमरनजीत कौर ने ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों, कानूनी संरक्षण एवं समान नागरिक संहिता से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तृत व स्पष्ट जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य महिलाओं में विधिक जागरूकता बढ़ाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा सामाजिक समानता की दिशा में सशक्त करना रहा।

उन्होंने महिलाओं को बताया कि विधिक सहायता कार्यक्रम के तहत न्यायालय में विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है तथा सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध

कराए जाते है। विभिन्न अपराधों के हेल्पलाइन नंबर की भी जानकारी दी गई। उन्होंने महिलाओं को किसी भी प्रकार की विधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।

कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार डॉ. ललित नारायण मिश्र द्वारा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि महिला सशक्तिकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर योजनाओं का लाभ लें तथा समाज में नेतृत्वकारी भूमिका निभाएं। उन्होंने ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए इसे सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बताया।

उन्होंने महिलाओं एवं पुरुषों के समान अधिकारों की आवश्यकता पर बल देते हुए समाज में समानता और न्याय की भावना को मजबूत करने की बात कही साथ ही उन्होंने महिलाओं से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने तथा उपलब्ध कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारों की जानकारी प्राप्त करने का आह्वान किया।

साइबर क्राइम की दी जानकारी

इस अवसर पर साइबर सेल से उप निरीक्षक अनीता शर्मा,उप निरीक्षक प्रकाश चंद एवं योगेश कैथोला ने साइबर अपराध से कैसे बचा जाए इसके बारे में महिलाओं को बताया कि अधिकतर साइबर अपराध लालच, डर या जल्दबाज़ी का फायदा उठाकर किए जाते हैं। अज्ञात कॉल या मैसेज के माध्यम से ह्ज्ञक्क बैंक विवरण, एटीएम पिन या क्ष्ठ जानकारी मांगना साइबर ठगी का सामान्य तरीका है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी स्थिति में अपनी गोपनीय जानकारी साझा न करे।

स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक

कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग से डॉ आरती ने बताया कि स्वस्थ शरीर एवं मानसिक विकास के लिए पौष्टिक आहार अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से किशोरियों एवं महिलाओं में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन एवं विटामिन की कमी से होने वाली समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने हरी सब्ज़ियों, फल, दालें, दूध एवं मोटे अनाज को दैनिक आहार में शामिल करने की सलाह दी। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी जानकारी दी। कहा कि जल्द ही 14 वर्ष तक की बालिकाओं को वैक्सीन भी लगाई जाएगी।

महिला कानूनों की दी जानकारी

कार्यशाला में हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने बताया कि आज कल घरेलू हिंसा बहुत बढ़ रही है जिसको लेकर महिलाओं को कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कैसे वो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे तथा ड्रग्स के बढ़ते चलन को देखते हुए कैसे बचे तथा ड्रग्स को बेचना,खरीदना कानूनी अपराध है। कार्यक्रम के अंत में जिला बाल विकास अधिकारी धर्मवीर सिंह द्वारा सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन संतोष रावत द्वारा किया गया।

चित्रकला के विजेताओं को किया सम्मानित

इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर बालिकाओं द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर मुख्य अतिथियों द्वारा मोनिका, यशिका सैनी, निर्मला, अनुष्का एवं प्रिया को स्मृति चिन्ह एव प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

कार्यशाला में सहायक परियोजना निदेशक नलिनीत घिल्डियाल, रमन सैनी ,विनीत चौधरी, योगिता सिंह, रेवती, सिद्धांत, मीनाक्षी सहित स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां, महिला प्रधान एवं विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सिडकुल पुलिस ने चोरी के सामान के साथ पकड़ा

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

थाना सिडकुल पुलिस ने एक अभियुक्त को चोरी के सामान के साथ पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक 29 जनवरी को वादी पजानी भागवतिप्पन की लिखित तहरीर पर अज्ञात चोर द्वारा वादी की कम्पनी ग्रापैनल्स कंपनी सिडकुल हरिद्वार का ताला तोड़कर पीतल व तांबा चोरी करने के संबंध में थाना सिडकुल पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त चोरी के अभियोग के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार के आदेशानुसार मुखबिर खास की सूचना पर हर्षिता कॉलोनी से आरोपी वसीम पुत्र शराफत निवासी जमालपुर खुर्द थाना कोतवाली रानीपुर जिला हरिद्वार को चोरी के माल के साथ तडियाल ढाबा सिडकुल के पास से पकडा गया। आरोपी के पास से 30 किलो टर्मिनल बुश और एक विक्रम बरामद किया।

मार्शल आर्ट गेम वुशु एवं सेल्फ डिफेंस की नेशनल कोच आरती सैनी ने उठाया जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का बीड़ा

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार प्रदेश की आम जनता के लिए कल्याणकारी नीतियों को बना रही है। उनका क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। लोकप्रिय जन नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य पुस्तिकाओं और कैलेंडरों के माध्यम से उत्तराखंड का सूचना एवं लोक संपर्क विभाग राज्य के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी के कुशल नेतृत्व में कुशलता के साथ कर रहा है। हरिद्वार जनपद में जिला अधिकारी मयूर दीक्षित के कुशल मार्ग निर्देशन में जिला सूचना अधिकारी रतीलाल शाह के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट वुशु एसोसिएशन हरिद्वार एवं डायनेमिक स्पोर्ट्स क्लब, मिस्सरपुर, हरिद्वार की सचिव, राष्ट्रीय कोच और सेल्फ डिफेंस की नेशनल ट्रेनर आरती सैनी ने पुष्कर सिंह धामी सरकार की जन नीतियों को सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित कैलेंडरों और पुस्तिका को जन-जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। आरती सैनी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपने खिलाड़ियों को साथ लेकर विभिन्न विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को आत्म सुरक्षा एवं मार्शल आर्ट वुशु का प्रशिक्षण देने

के साथ-साथ उन्हें सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित कैलेंडरों और पुस्तिकाओं का व्यापक स्तर पर वितरण किया। विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षकों और आरती सैनी ने पुस्तिका में प्रकाशित उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की जन प्रिय लोकप्रिय नीतियों के बारे में छात्र-छात्राओं को अवगत कराया और सरकार की विभिन्न उपलब्धियां के बारे में प्रकाश डाला। प्रथम चरण में श्यामपुर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज एवं आदर्श इंटर कॉलेज में पुस्तिकाओं एवं कैलेंडरों को वितरित करने का कार्य किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज श्यामपुर के प्रधानाचार्य महेंद्र लाल ने बताया कि विद्यालय में उत्तराखंड सरकार की विकास पुस्तिका एवं कैलेंडर वितरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। आदर्श इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अभिषेक पेन्यूली ने बताया कि विद्यालय में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित कैलेंडर और पुस्तिकाओं का वितरण किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज श्यामपुर की छात्रा आरुषि रावत का कहना है कि इन विकास पुस्तिकाओं और कैलेंडरों के माध्यम से हमें उत्तराखंड की लोकप्रिय पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा लागू की गई महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में कई जानकारी मिली है।

हरिद्वार नगर निगम की हेल्पलाइन: कुत्तों से जुड़ी शिकायतों के लिए एक कॉल पर निदान

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

शहर में कुत्तों (डॉग) से संबंधित समस्याओं के प्रभावी, संवेदनशील एवं समयबद्ध समाधान की दिशा में नगर निगम हरिद्वार ने एक अहम पहल की है। नगर निगम ने स्ट्रीट डॉग मैनेजमेंट, एबीसी (एनिमल बर्थ कंट्रोल) सहित कुत्तों से जुड़ी सभी प्रकार की शिकायतों के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 9568844151 जारी किया है।

नगर निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली शिकायतों पर नगर निगम हरिद्वार की अनुबंधित संस्था एचएसआई (॥ह्वद्वड्ढठ्ठ स्थ्यष्द्बद्गह्ल4 द्धठ्ठह्लद्गह्लठ्ठड्डह्लद्बश्ठ्ठड्डद्य) द्वारा कार्रवाई की जाएगी। शिकायत दर्ज कराते समय शिकायतकर्ता को समस्या का प्रकार, पूरा पता तथा संपर्क विवरण देना अनिवार्य होगा, ताकि संबंधित टीम मौके पर पहुंचकर शीघ्र और सटीक समाधान सुनिश्चित कर सके। प्राप्त शिकायतों की प्रक्रिया के तहत एचएसआई की टीम सबसे पहले शिकायतकर्ता से फोन के माध्यम से संपर्क कर शिकायत की पुष्टि करेगी। इसके पश्चात फील्ड टीम मौके पर जाकर आवश्यक कार्रवाई करेगी। कार्रवाई पूर्ण होने के बाद शिकायतकर्ता को समस्या की स्थिति एवं समाधान की जानकारी भी दी जाएगी, जिससे शिकायत निस्तारण में पारदर्शिता बनी रहे। इस पूरी व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन के लिए नगर निगम हरिद्वार में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गंभीर सिंह तलियान को नोडल अधिकारी तथा मुख्य सेनेटरी इंस्पेक्टर श्रीकांत चौधरी को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

इस अवसर पर नगर आयुक्त नंदन कुमार (आईएएस) ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य कुत्तों से संबंधित समस्याओं का समाधान पूरी तरह मानवीय, वैज्ञानिक और समयबद्ध तरीके से करना है। उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा तथा एबीसी कार्यक्रम सहित सभी आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित की जाएंगी। नगर आयुक्त ने आमजन से अपील की कि वे सहयोग करते हुए कुत्तों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए निर्धारित हेल्पलाइन नंबर का ही उपयोग करें। नगर निगम प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि शिकायत निस्तारण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए शीघ्र ही नगर निगम एवं एचएसआई के संयुक्त तत्वावधान में कम्प्लेंट मैनेजमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। इस वर्कशॉप के माध्यम से शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान की प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया जाएगा। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे कुत्तों से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए सीधे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, जिससे शहर में सुव्यवस्थित, सुरक्षित और मानवीय डॉग मैनेजमेंट सुनिश्चित किया जा सके।

एक नजर

सिडकुल पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन, नशीले कैप्सूल के साथ एक गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। सिडकुल थाना पुलिस थानाध्यक्ष नितेश शर्मा के नेतृत्व में नशा तस्करों के विरुद्ध लगातार अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत सिडकुल पुलिस ने एक अभियुक्त को पकड़ा जिसके पास से अवैध नशे के कैप्सूल बरामद हुए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार द्वारा अवैध मादक पदार्थ (अवैध शराब/स्मैक/चरस/गांजा/नशीली दवाइयां/इंजेक्शनआदि) तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान को सफल बनाने हेतु थानाध्यक्ष सिडकुल को निर्देशित किया गया। थानाध्यक्ष सिडकुल द्वारा उक्त आदेश के क्रम में थाना क्षेत्रांतर्गत अलग अलग टीमों का गठन किया गया,गठित टीमो को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आदेश के क्रम में 31 जनवरी को मुखबिर खास की सूचना पर टीम द्वारा आरोपी अभिजीत पुत्र मनिमोहन रॉय निवासी पीर वाली गली राजीव नगर आर्य नगर ज्वालापुर थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार आईएमसी चौक सिडकुल हरिद्वार से पकडा गया। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। उसके पास से 240 कैप्सूल TRAMADOL बरामद हुए। पुलिस ने उसकी स्कूटी को भी अपने कब्जे में ले लिया है।

हरिद्वार पुलिस ने चोरी की योजना बनाते चार अभियुक्तों को पकड़ा

पथ प्रवाह, हरिद्वार। हरिद्वार पुलिस ने चोरी की योजना बनाकर घटना को अंजाम देने से पहले ही आरोपियों के मंसूबों कपर पानी फेर दिया। पुलिस ने चार अभियुक्तों को आला नकब के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी टोली बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। नशे की पूर्ति के लिए आरोपी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक 30-31/01/2026 की रात्रि को थाना क्षेत्रान्तर्गत रात्री गश्त में के दौरान पुलिस टीम द्वारा 04 आरोपियो 1.मोहित कुमार पुत्र मैनपाल (कब्जे से 01 छोटी टार्च) 2- शुभम पुत्र यशपाल (कब्जे एक अदद पेचकस) 3- अंकुर पुत्र गिरधारी लाल (कब्जे से लोहे काटने वाला आरी का ब्लैड),4- रोहित पुत्र पहल सिह (कब्जे से एक लोहे का प्लास) को इब्राहिमपुर जाने वाले मार्ग के पास खण्डहर से पकडा गया। आरोपियो के विरूद्ध गंगनहर पर प्रभावी धाराओ में अभियोग दर्ज किया गया ।

सेवानिवृत्त हुए आईजी एन.एस. नपलच्याल व डीएसपी नवीन चन्द्र सेमवाल

पथ प्रवाह, देहरादून।

अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के अवसर पर पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून स्थित सभागार में पुलिस महानिरीक्षक एन.एस. नपलच्याल एवं पुलिस उपाधीक्षक नवीन चन्द्र सेमवाल के सम्मान में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह भावनात्मक वातावरण और सम्मानपूर्ण गरिमा के साथ सम्पन्न हुआ।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड दीपम सेठ, अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) वी. मुरुगेशन, अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) ए.पी. अंशुमान सहित पुलिस विभाग के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। समारोह के दौरान वक्ताओं ने दोनों अधिकारियों की दीर्घ, निष्कलंक एवं गौरवशाली सेवा यात्रा का उल्लेख करते हुए उनके कर्तव्यनिष्ठ योगदान, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता एवं उत्कृष्ट कार्यशैली की भूरि-भूरि प्रशंसा की। वक्ताओं ने कहा कि दोनों अधिकारियों ने अपने सेवाकाल में विभागीय मूल्यों को सर्वोपरि रखते हुए उत्तराखण्ड पुलिस की छवि को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर अपने संबोधन में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कहा कि सेवानिवृत्त हो रहे वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रत्येक दायित्व को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और गरिमा के साथ निभाया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इनके अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ भविष्य में भी उत्तराखण्ड पुलिस को मिलता रहेगा। डीजीपी ने उत्तराखण्ड पुलिस परिवार की ओर से दोनों अधिकारियों के समर्पित सेवाकाल के लिए आभार व्यक्त करते हुए उनके स्वस्थ, सुखद एवं सक्रिय भविष्य की मंगलकामनाएं दीं। अपने संबोधन में एन.एस. नपलच्याल एवं नवीन चन्द्र सेमवाल ने भी विभागीय अधिकारियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सहयोग, विश्वास और टीम भावना के कारण ही वे अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सके। पुलिस महानिदेशक द्वारा दोनों सेवानिवृत्त अधिकारियों को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया।

सेवा विवरण – एन.एस. नपलच्याल

एन.एस. नपलच्याल का चयन वर्ष 1995 में प्रांतीय पुलिस सेवा में हुआ। उन्होंने उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल, मेरठ तथा पीटीसी मुरादाबाद सहित अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर सेवाएं दीं। भारतीय पुलिस सेवा में इंडक्शन के पश्चात् उन्होंने वर्ष 2012-13 में संयुक्त राष्ट्र मिशन, सूडान में भी सेवाएं प्रदान कीं। वर्ष 2019 में पुलिस उप महानिरीक्षक तथा वर्ष 2023 में पुलिस महानिरीक्षक पद पर पदोन्नति के उपरान्त उन्होंने फायर, प्रशिक्षण, सीआईडी एवं निदेशक यातायात जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र मेडल, वर्ष 2019 में राष्ट्रपति सराहनीय सेवा पदक तथा वर्ष 2025 में राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

सेवा विवरण – नवीन चन्द्र सेमवाल

नवीन चन्द्र सेमवाल ने वर्ष 1985 में पुलिस विभाग में आरक्षी पद से सेवाकाल प्रारम्भ किया। वे वर्ष 1998 में उप निरीक्षक, 2016 में निरीक्षक तथा 2024 में पुलिस उपाधीक्षक पद पर पदोन्नत हुए। उन्होंने नैनीताल, मेरठ, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार एवं पुलिस मुख्यालय में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2025 में सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। विदाई समारोह में उपस्थित अधिकारियों ने दोनों सेवानिवृत्त अधिकारियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनके योगदान को उत्तराखण्ड पुलिस के लिए प्रेरणास्रोत बताया।

हरिद्वार पुलिस से सेवानिवृत्त हुए 2 सदस्यों को दी गई भावभीनी विदाई

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जनपद हरिद्वार में नियुक्त उत्तराखण्ड पुलिस के 2 सदस्यों के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के अवसर पर पुलिस कार्यालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में विदाई समारोह आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल, एसपी क्राईम जितेन्द्र मेहरा, एसपी/क्षेत्राधिकारी लाइन निशा यादव, एसपी/क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर जितेन्द्र चौधरी सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में सेवानिवृत्त हुए दोनों सदस्यों को फूल माला पहनाकर स्मृति चिन्ह आदि भेंट किए गए।

जलपान के दौरान सेवानिवृत्त हो रहे दोनों सदस्यों सहित तमाम अधिकारियों ने गुजरे कल के यादगार लम्हों को पुनः याद कर उनकी स्मृति ताजा की। परिजनों की मौजूदगी में ये पल सभी के लिए विशेष क्षण लेकर आए।

सेवानिवृत्त हुए सदस्यों में वर्ष 1987 में बतौर फायरमैन पुलिस विभाग का हिस्सा बने जब्बार खां वर्ष 2013 में लीडिंग फायर मैन व वर्ष 2025 में एफएसएसओ के पद पर पदोन्नत हुए व लगभग 38 वर्षों की विभागिय सेवा उपरांत आज सेवानिवृत्त हुए। वहीं मूल रूप से जनपद पौड़ी के निवासी राजेश वर्ष 1989 में पुलिस विभाग में बतौर फायरमैन भर्ती होकर वर्ष 2017 में लीडिंग फायर मैन के पद पर पदोन्नत हुए व करीब 36 वर्ष की विभागिय सेवा के पश्चात आज सेवानिवृत्त हुए।

संपादकीय

दिखावे की भव्यता बनाम गंगा की वास्तविक सुरक्षा

आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर सरकार और प्रशासन भव्यता, ब्रांडिंग और प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। करोड़ों रुपये के बजट, चमचमाते होर्डिंग्स, स्वागत द्वार और इवेंट मैनेजमेंट की योजनाएँ बनाई जा रही हैं। लेकिन इसी बीच गंगा जैसी जीवनदायिनी नदी के संरक्षण के लिए जब बुनियादी इंतजामों की बात आती है, तो 'बजट की कमी' का बहाना सामने आ जाता है। यह स्थिति न केवल गंभीर है, बल्कि गहरे विरोधाभास और प्रशासनिक असंवेदनशीलता को भी उजागर करती है।

गंगा में सामग्री विसर्जन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (हृतञ्ज) द्वारा स्पष्ट और सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद पुलों पर लगी जालियों का टूटना, उनका रखरखाव न होना और निगरानी व्यवस्था का कमजोर पड़ना सीधे-सीधे इन आदेशों की अवहेलना है। पुलों पर ऊँची जालियाँ (स्द्गद्यद्ध द्धद्बद्धद्ग) लगाने का उद्देश्य ही यही था कि लोग फूल, पूजा-सामग्री और अन्य अपशिष्ट नदी में न फेंक सकें। यदि प्रशासन यह कहता है कि इनके लिए धन उपलब्ध नहीं है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि पर्यावरण संरक्षण प्रशासन की प्राथमिकता सूची में आखिर कहाँ है।

आज स्थिति यह है कि एक ओर 'छवि निर्माण' पर जोर है और दूसरी ओर गंगा की 'सेहत' लगातार अनदेखी का शिकार हो रही है। सच यह है कि नदी की सफाई और संरक्षण पोस्टरों, बैनरों या नारों से नहीं होता, बल्कि ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर और सख्त प्रवर्तन से होता है। कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ेगी। यदि अभी से प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई, तो कुंभ के बाद गंगा की स्थिति और भी भयावह हो सकती है।

समाधान असंभव नहीं हैं, बशर्ते प्रशासन अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करे। कुंभ के प्रचार-प्रसार के बजट का एक छोटा सा हिस्सा भी यदि पुलों पर जालियों की मरम्मत, नई जालियों की स्थापना और सीसीटीवी निगरानी पर खर्च कर दिया जाए, तो बड़ा बदलाव संभव है। इसके साथ ही पुलों पर होमगार्ड, स्वयंसेवक या 'पर्यावरण प्रहरी' की तैनाती जरूरी है, जो लोगों को सामग्री फेंकने से रोक सकें। केवल चेतावनी बोर्ड लगाने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती।

सबसे अहम है विकल्प उपलब्ध कराना। पुलों और घाटों के पास 'समर्पण पात्र' या कलेक्शन बिन रखे जाएँ, जहाँ श्रद्धालु अपनी धार्मिक सामग्री छोड़ सकें। बाद में इनका वैज्ञानिक और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से निस्तारण किया जाए। यही सच्ची श्रद्धा और वास्तविक सुशासन का प्रतीक होगा।

कुंभ की भव्यता तभी सार्थक है, जब गंगा स्वच्छ और सुरक्षित हो। अन्यथा यह उत्सव केवल दिखावे का आयोजन बनकर रह जाएगा, जिसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी।

केन्द्र सरकार की आम बजट 2026: उम्मीदों की झोली या उपेक्षा का दस्तावेज

विनोद कुमार सिंह

देश की धड़कन संसद में,जनता की निगाहें वित्त मंत्री सीता रमण परकुछ ही घंटे शेष हैं।संसद के भीतर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण तैयार है और संसद के बाहर पूरा देश सांस रोके बैठा है।1 फरवरी 2026 को पेश होने वाला आम बजट केवल सरकारी खाते-बही का दस्तावेज नहीं,बल्कि करोड़ों नागरिकों की उम्मीदों,आशंकाओं और अपेक्षाओं की कसौटी है।यह वही घड़ी है जब तय होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण में खींची गई तस्वीर को वित्त मंत्री कितनी मजबूती देती हैं और क्या यह बजट सचमुच जनता के जीवन में राहत की बारिश करेगा या फिर आंकड़ों की चकाचौंध में आम आदमी को एक बार फिर खाली हाथ लौटना पड़ेगा।आर्थिक सर्वेक्षण ने तस्वीर रख दी,अब बजट जवाब देगा।आर्थिक सर्वेक्षण ने एक तरफ भारत की मजबूत जीडीपी ग्रोथ,नियंत्रित महंगाई और वैश्विक अस्थिरता के बीच देश की स्थिरता को रेखांकित किया है।वित्त मंत्री ने स्वयं कहा है कि भारत दुनिया के लिए 'ग्लोबल ब्राइट स्पॉट' है। 2025-26 में 7.4 प्रतिशत विकास दर का अनुमान भारत को लगातार चौथे वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाता है।लेकिन सवाल यह है - क्या यह चमक आम आदमी के घर तक पहुंची है? क्या विकास के ये आंकड़े किसान की खेत-मेड़ पर,मजदूर की थाली में और युवा की नौकरी में बदल पाए हैं?अर्थव्यवस्था की तस्वीर जितनी उजली है,चुनौतियां उतनी ही गहरी हैं। रोजगार,ग्रामीण मांग,राज कोषीय घाटा और महंगाई–ये ऐसे मोर्चे हैं जहां सिर्फ भाषण नहीं, ठोस फैसले चाहिए।आम आदमीः हर बजट में सबसे बड़ा दर्शक,सबसे बड़ा पीड़ित हर वर्ष बजट आता है और हर वर्ष आम आदमी वही सवाल पूछता है– 'इस बार मेरे लिए क्या?' महंगाई ने ग्रहणी की रसोई को जकड़ रखा है।शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च लगातार बढ़ रहा है।मध्यम वर्ग टैक्स के बोझ से दबा है।गरीब कल्याण योजनाओं पर निर्भर है।आम बजट का असली मतलब तभी होगा जब यह आम आदमी के जीवन में राहत लाएगा।वरना यह 'आम बजट' नहीं, सिर्फ सरकारी औपचारिकता बनकर रह जाएगा।मध्यम वर्गः टैक्स राहत नहीं मिली तो नाराजगी तय है।मध्यम वर्ग इस बजट की सबसे बड़ी उम्मीद है और सबसे बड़ा दबाव भी।इस वर्ग को इनकम टैक्स में राहत,स्लैब में बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने और होम लोन ब्याज छूट की सीमा बढ़ने की आस है। ऐसे मे क्या सरकार इस वर्ग को राहत देगी या फिर एक बार फिर 'धैर्य रखिए' कहकर टाल देगी?

दिलचस्प बात यह है कि गूगल ट्रेंड्स बताता है कि बजट के दिनों में 'इनकम टैक्स' से ज्यादा 'बजट' शब्द सर्च होता है।यानी जनता सिर्फ टैक्स नहीं, पूरे भविष्य का जवाब चाहती है।किसानः सम्मान निधि बढ़ेगी या सिर्फ आश्वासन मिलेगा? -देश का किसान इस बजट की सबसे बड़ी निगाह है। उम्मीद की जा रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये की जा सकती है।सरकार बताती है कि 11 करोड़ किसानों को अब तक 4.09 लाख करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

लेकिन सवाल यह है–क्या यह पर्याप्त है? किसान आज भी खाद-बीज की कीमतों, सिंचाई की कमी और एमएसपी की अनिश्चितता से जूझ रहा है।

यदि बजट किसान को केवल योजनाओं के आंकड़े देगा,तो यह राहत नहीं,छलावा कहलाएगा।

महिलाएंः लाभार्थी नहीं,भागीदार बनें - महिलाओं को उम्मीद है कि उज्वला जैसी योजनाओं का विस्तार होगा, महिला उद्यमियों को सस्ते लोन मिलेंगे और कामकाजी महिलाओं के लिए टैक्स में विशेष छूट आएगी।यहाँ पर सवाल उठना स्वाभाविक है– क्या बजट महिलाओं को केवल लाभार्थी बनाएगा या आर्थिक विकास की असली भागीदार?यदि महिला सशक्तिकरण सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहा, तो यह भी उपेक्षा का ही दूसरा नाम होगा।युवाः रोजगार चाहिए,भाषण नहीं देश का युवा आज सबसे बड़ा प्रश्न है।स्टार्टअप्स,स्किल डेवलपमेंट,शिक्षा ऋण में राहत और रोजगार सृजन–यही उनकी अपेक्षा है।लेकिन युवा को अब 'भविष्य उज्ज्वल है' जैसे वाक्य नहीं चाहिए।उसे नौकरी चाहिए,अवसर चाहिए,स्थिरता चाहिए।अगर बजट रोजगार के मोर्चे पर ठोस कदम नहीं उठाता, तो विकास दर के सारे आंकड़े खोखले साबित होंगे।कर्मचारी और पेंशनर्सः 8वें वेतन आयोग का इंतजार -सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बजट भाषण बेहद महत्वपूर्ण है।8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए यदि बजट में फंड का प्रावधान हुआ,तो उम्मीदें पंख पकड़ेंगी।वरना यह वर्ग भी खुद को उपेक्षित महसूस करेगा।बाजार और निवेशकः बजट का असर सिर्फ शेयर नहीं,भरोसे पर भी बजट से पहले सोने-चांदी में भारी गिरावट बाजार की बेचैनी का संकेत है।निवेशकों के लिए बजट अनिश्चितता और अवसर दोनों है।

एसबीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट बताती है कि बजट के बाद बाजार में 70 प्रतिशत से ज्यादा बार रिकवरी देखी गई है।बाजार का असली आधार भरोसा है, और भरोसा तभी टिकेगा जब बजट में स्थिरता और स्पष्ट दिशा होगी।

बजट 2026ः बड़ा धमाका या धीमी रणनीति? -एमके ग्लोबल ने इसे 'लो-इम्पैक्ट इवेंट' कहा है। बड़े सुधार पहले ही हो चुके हैं, इसलिए नई घोषणाओं की गुंजाइश सीमित है।जनता को 'गुंजाइश' नहीं चाहिए,उसे राहत चाहिए।उसे भरोसा चाहिए कि सरकार विकास को जमीन पर उतारेगी।संक्षेप हम कह सकते है कि यह बजट जनता की झोली भरेगा या उम्मीदें फिर टाल देगा?देश की स्थिति उस किसान जैसी है जो आसमान की ओर देख रहा है–बारिश होगी या नहीं।आम बजट 2026 से अपेक्षा है कि

जीवन सस्ता हो रोजगार बढ़े, किसान मजबूत हो, महिलाएं सशक्त हों और मध्यम वर्ग को राहत मिले,लेकिन अगर यह बजट सिर्फ आंकड़ों और योजनाओं का दस्तावेज बनकर रह गया,तो यह 'आम बजट' नहीं, 'उपेक्षा बजट' कहलाएगा।अब फैसला संसद में होगा। कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा कि यह बजट जनता की उम्मीदों का पर्व बनता है या एक और अधूरी कहानी।

15वीं सदी के महान समाज सुधारक थे संत रविदास

योगेश कुमार गोयल

समस्त भारतीय समाज को भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता और भाईचारे की सीख देने वाले 15वीं सदी के महान् समाज सुधारक संत रविदास का जन्म वाराणसी के गोवर्धनपुर गांव में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के ही दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को है, इसीलिए इसी दिन संत रविदास जयंती मनाई जा रही है। महान् संत, समाज सुधारक, साधक और कवि रविदास ने जीवन पर्यन्त छुआछूत जैसी कुरीतियों का विरोध करते हुए समाज में फैली तमाम बुराईयों के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई और उन कुरीतियों के खिलाफ निरन्तर कार्य करते रहे। उनका जन्म ऐसे विकट समय में हुआ था, जब समाज में घोर अंधविश्वास, कुप्रथाओं, अन्याय और अत्याचार का बोलबाला था, धार्मिक कट्टपंथता चरम पर थी, मानवता कराह रही थी। उस जमाने में मध्यमवर्गीय समाज के लोग कथित निम्न जातियों के लोगों का शोषण किया करते थे। ऐसे विकट समय में समाज सुधार की बात करना तो दूर की बात, उसके बारे में सोचना भी मुश्किल था लेकिन जूते बनाने का कार्य करने वाले संत रविदास ने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने के लिए समाधि, ध्यान और योग के मार्ग को अपनाते हुए असीम ज्ञान प्राप्त किया और अपने इसी ज्ञान के जरिये पीड़ित समाज एवं दीन-दुखियों की सेवा कार्य में जुट गए। उन्होंने अपनी सिद्धियों के जरिये समाज में व्याप्त आडम्बरों, अज्ञानता, झूठ, मक्कारी और अधार्मिकता का भंडाफोड़ करते हुए समाज को जागृत करने और नई दिशा देने का प्रयास किया। संत रविदास को 'रैदास' के नाम से भी जाना जाता है। वे गंगा मैया के अनन्य भक्त थे। संत रविदास को लेकर 'मन चंगा तो कठौती में गंगा' कहावत बहुत प्रचलित है। इस कहावत का संबंध संत रविदास की महिमा को परिलक्षित करता है। वे जूते बनाने का कार्य किया करते थे और इस कार्य से उन्हें जो भी कमाई होती, उससे वे संतों की सेवा किया करते और उसके बाद जो कुछ बचता, उसी से परिवार का निर्वाह करते थे। एक दिन रविदास जूते बनाने में व्यस्त थे कि तभी उनके पास एक ब्राह्मण आया और उनसे कहा कि मेरे जूते टूट गए हैं, इन्हें ठीक कर दो। रविदास उनके जूते ठीक करने लगे और उसी दौरान उन्होंने ब्राह्मण से पूछ लिया कि वे कहां जा रहे हैं? ब्राह्मण ने जवाब दिया, ''मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं पर चमड़े का काम करने वाले तुम क्या जानो कि इससे कितना पुण्य मिलता है!'' इस पर रविदास जी ने कहा कि आप सही कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, हम नीच और मलिन लोगों के गंगा स्नान करने से गंगा अपवित्र हो जाएगी। जूते ठीक होने के बाद ब्राह्मण ने उसके बदले उन्हें एक कौड़ी मूल्य देने का प्रयास किया तो संत रविदास ने कहा कि इस कौड़ी को आप मेरी ओर से गंगा मैया को 'रविदास की भेंट' कहकर अर्पित कर देना।

ब्राह्मण गंगाजी पहुंचा और स्नान करने के पश्चात् जैसे ही उसने रविदास द्वारा दी गई मुद्रा यह कहते हुए गंगा में अर्पित करने का प्रयास किया कि गंगा मैया रविदास की यह भेंट स्वीकार करो, तभी जल में से स्वयं गंगा मैया ने अपना हाथ निकालकर ब्राह्मण से वह मुद्रा ले ली और मुद्रा के बदले ब्राह्मण को एक सोने का कंगन देते हुए वह कंगन रविदास को देने का कहा। सोने का रत्न जड़ित अत्यंत सुंदर कंगन देखकर ब्राह्मण के मन में लालच आ गया और उसने विचार किया कि घर पहुंचकर वह यह कंगन अपनी पत्नी को देगा, जिसे पाकर वह बेहद खुश हो जाएगी। पत्नी ने जब वह कंगन देखा तो उसने सुझाव दिया कि क्यों न रत्न जड़ित यह कंगन राजा को भेंट कर दिया जाए, जिसके बदले वे प्रसन्न होकर हमें मालामाल कर देंगे। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण राजदरबार पहुंचा और कंगन राजा को भेंट किया तो राजा ने ढ़ेर सारी मुद्राएं देकर उसकी झोली भर दी। राजा ने प्रेमपूर्वक वह कंगन अपनी महारानी के हाथ में पहनाया तो महारानी इतना सुंदर कंगन पाकर इतनी खुश हुई कि उसने राजा से दूसरे हाथ के लिए भी वैसे ही कंगन की मांग की। राजा ने अगले ही दिन ब्राह्मण को दरबार बुलाया और उसे वैसा ही एक और कंगन लाने का आदेश देते हुए कहा कि अगर उसने तीन दिन में कंगन लाकर नहीं दिया तो वह दंड का पात्र बनेगा। राजाज्ञा सुनकर बेचारे ब्राह्मण के होश उड़ गए। वह गहरी सोच में डूब गया कि आखिर दूसरा कंगन वो कहां से लाएगा? उसे जब और कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने निश्चय किया कि वह संत रविदास के पास जाकर उन्हें सारे वाकये की जानकारी देगा कि कैसे गंगा मैया ने स्वयं यह कंगन उसे उन्हें देने के लिए दिया था, जो उसने लोभवश अपने पास रख लिया।

आर्थिक सर्वेक्षण से बजट तक : भविष्य के भारत की तलाश

ललित गर्ग

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद के पटल पर प्रस्तुत किया जाने वाला बजट केवल आय-व्यय का वार्षिक लेखा-जोखा नहीं होता, बल्कि वह देश की आर्थिक दिशा, सामाजिक प्राथमिकताओं और भविष्य की संभावनाओं का दर्पण होता है। आज जब भारत एक ओर तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व मंच पर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है और दूसरी ओर वैश्विक अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनावों, जलवायु संकट और तकनीकी परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब यह बजट और भी अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। व्यक्तिगत नागरिक से लेकर व्यापारी, उद्योगपति, किसान, श्रमिक, युवा और मध्यम वर्ग-सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हैं, क्योंकि इससे न केवल वर्तमान वर्ष की आर्थिक तस्वीर, बल्कि 'भविष्य के भारत' की झलक भी मिलती है।

बजट से पूर्व प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण ने सरकार की सोच और नीति-दृष्टि के कई संकेत दिए हैं। इसमें विकास को केवल आंकड़ों की वृद्धि तक सीमित न रखकर अवसरों के विस्तार, समावेशी विकास और दीर्घकालिक स्थिरता पर जोर दिया गया है। यह स्वीकार किया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां अवश्य हैं, किंतु उनसे अधिक संभावनाएं हैं। यही दृष्टिकोण इस बजट का मूल स्वर होना चाहिए-चुनौतियों को अवसरों में बदलने का साहसिक प्रयास।

सबसे पहली और महत्वपूर्ण अपेक्षा निम्न वर्ग की क्रय-शक्ति बढ़ाने को लेकर है। किसी भी अर्थव्यवस्था की वास्तविक मजबूती तभी आती है जब उसके सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी सम्मानजनक जीवन जी सके और उपभोग में भागीदार बने। यदि निम्न आय वर्ग की आय बढ़ती है, उसे सस्ती और सुलभ सुविधाएं मिलती हैं, तो उसका सीधा प्रभाव मांग पर पड़ता है और मांग बढ़ने से उत्पादन, निवेश और रोजगार-तीनों को गति मिलती है। इसलिए इस बजट में प्रत्यक्ष नकद अंतरण, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च के साथ-साथ रोजगार सृजन के ठोस उपाय अपेक्षित हैं। मनरेगा जैसे कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण, शहरी गरीबों के लिए भी समान प्रकृति की योजनाएं और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।

शहरी विकास इस बजट का एक और प्रमुख केंद्र होना चाहिए। भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है और शहरों पर जनसंख्या, आवास, परिवहन, जल, स्वच्छता और पर्यावरण का दबाव लगातार बढ़ रहा है। केवल बड़े महानगरों पर निर्भरता अब व्यावहारिक नहीं रही। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा द्वारा सुझाया गया शहरी विकेंद्रीकरण का विचार आज के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। छोटे और मध्यम शहरों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाना, उद्योगों और सेवाओं को वहां प्रोत्साहित करना, न केवल महानगरों पर बोझ कम करेगा बल्कि क्षेत्रीय असंतुलन को भी घटाएगा। बजट में यदि टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए विशेष शहरी अवसंरचना पैकेज, परिवहन नेटवर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी और कौशल विकास योजनाएं लाई जाती हैं, तो यह दूरगामी परिवर्तन का आधार बन सकता है।

वैश्विक स्तर पर टैरिफ, व्यापार अवरोध और संरक्षणवाद की प्रवृत्तियां भारत के लिए चुनौती भी हैं और अवसर भी। अजय बंगा का यह कथन कि टैरिफ पर अधिक चिंता करने के बजाय व्यापारिक अवसरों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, भारत की वर्तमान स्थिति के लिए उपयुक्त दृष्टि प्रदान करता है। भारत के पास विशाल घरेलू बाजार, युवा जनसंख्या, डिजिटल क्षमताएं और उद्यमशीलता की प्रबल ऊर्जा है। यदि यह बजट निर्यात-उन्मुख उद्योगों, स्टार्ट-अप्स, मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू-एडेड सेक्टर को प्रोत्साहन देता है, तो भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में और मजबूत स्थान बना सकता है। 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को केवल नारों से आगे ले जाकर व्यावहारिक नीति समर्थन की आवश्यकता है-सरल कर संरचना, आसान ऋण, अनुसंधान एवं नवाचार में निवेश और व्यापार करने में सुगमता के माध्यम से।

इस संदर्भ में मध्यम वर्ग की भूमिका को नजरअंदाज करना आर्थिक दृष्टि से आत्मघाती होगा। मध्यम वर्ग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है-वह सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा करदाता भी। विडंबना यह है कि बजट चर्चाओं में अक्सर यही वर्ग अपेक्षाकृत उपेक्षित रह जाता है। बढ़ती महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च, आवास ऋण और करों का बोझ मध्यम वर्ग की बचत और उपभोग दोनों को प्रभावित करता है। यदि इस बजट में आयकर स्लैब में तर्कसंगत सुधार, शिक्षा-स्वास्थ्य पर कर राहत और आवास को प्रोत्साहन जैसे कदम उठाए जाते हैं, तो इससे न केवल मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी बल्कि मांग-आधारित विकास को भी बल मिलेगा।

उद्योगों और व्यापार जगत के लिए बजट से अपेक्षा है कि वह स्थिर और पूर्वानुमेय नीति वातावरण प्रदान करे। निवेशक अनिश्चितता से डरते हैं।

मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उत्तराखण्ड की सबसे सशक्त और प्रभावी प्रस्तुति

पथ प्रवाह, देहरादून।

छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 17वीं बैठक में उत्तराखण्ड राज्य ने विकास से जुड़े मुद्दों को मजबूती और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर विशेष पहचान बनाई। बैठक में उत्तराखण्ड द्वारा कुल 13 महत्वपूर्ण विषय रखे गए, जो अन्य सभी सदस्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक रहे। उत्तराखण्ड की प्रस्तुति पर केंद्र सरकार द्वारा सकारात्मक रुख व्यक्त करते हुए समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।

यह बैठक उत्तराखण्ड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि इसमें न केवल राज्य की विकासात्मक आवश्यकताओं और चुनौतियों को केंद्र स्तर पर प्रभावी ढंग से रखा गया, बल्कि इससे अंतर्राज्यीय समन्वय और क्षेत्रीय सहयोग को भी नई गति मिली। बैठक में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री तथा वन एवं पर्यावरण आरके सुधांशु के नेतृत्व में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक में सदस्य राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के साथ-साथ केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान चारों राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, लंबित मामलों के समाधान तथा आपसी समन्वय को मजबूत करने से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री तथा वन एवं पर्यावरण आरके सुधांशु ने बैठक को अत्यंत प्रभावी बताते हुए कहा कि उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत सभी बिंदुओं को ठोस तर्कों, व्यावहारिक दृष्टिकोण और राज्य की भौगोलिक एवं आपदा-संवेदनशील परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रखा गया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने इन विषयों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पूर्व में वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उठाए गए 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस बैठक में पुनः समीक्षा हेतु यथावत रखा गया था। बैठक में इन विषयों की प्रगति की समीक्षा की गई, जिनमें खाद्य सुरक्षा उपाय, महिलाओं और बच्चों से जुड़े यौन अपराध एवं पाक्सो मामलों पर कार्यवाही, फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की रोकथाम, ईआरएसएस 112, सहकारिता को सशक्त बनाने के उपाय, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी गांवों के पांच किलोमीटर के दायरे में बैंक शाखा या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना जैसे विषय शामिल रहे। बैठक के दौरान राज्यों द्वारा अपनाई जा रही नवाचारपूर्ण पहलों और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर भी चर्चा हुई। उत्तराखण्ड द्वारा तीन प्रमुख बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रस्तुत की गईं, जिनमें State to Pitch Supply Chain Plan, डिजिटल शिक्षा प्रबंधन प्रणाली (DEMS) तथा सारा परियोजना के अंतर्गत जल स्रोतों एवं नदियों के पुनर्जीवन (Spring and River Rejuvenation) से संबंधित कार्य शामिल रहे। अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ द्वारा भी तीन-तीन प्रस्तुतीकरण दिए गए। बैठक में उत्तराखण्ड की प्रस्तुतियों को विशेष रूप से सराहा गया। इस बैठक में राज्य की ओर से प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण आरके सुधांशु, सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम, सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन, सचिव सामान्य प्रशासन राजेंद्र कुमार, विशेष सचिव गृह निवेदिता कुकरेती तथा विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते ने प्रतिभाग किया।

बैठक से योजनाओं के क्रियान्वयन को मिलेगी गति : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक राज्यों के बीच समन्वय को सशक्त करने और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रभावी मंच है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड ने इस बैठक में विकास, आधारभूत संरचना, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े विषयों को प्राथमिकता के साथ प्रस्तुत किया है। परिषद के माध्यम से प्राप्त सुझावों और सहमति के आधार पर राज्य में योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

मुख्य सचिव के नेतृत्व में हुई थी व्यापक तैयारी

उत्तराखण्ड द्वारा रखे जाने वाले बिंदुओं के संबंध में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन द्वारा सभी विभागों के साथ पृथक-पृथक बैठकें कर प्रभावी तैयारी कराई गई थी। इसके परिणामस्वरूप पहली बार उत्तराखण्ड की ओर से अधिकतम 13 विषय परिषद में प्रस्तुत किए गए, जबकि छत्तीसगढ़ द्वारा 4, मध्य प्रदेश द्वारा 5 और उत्तर प्रदेश द्वारा 3 विषय रखे गए। उत्तराखण्ड ने सामाजिक, आधारभूत संरचना और आपदा-संवेदनशील परिस्थितियों से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाया। इनमें प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज स्थापना हेतु मानकों में संशोधन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में वृद्धि, निराश्रित गोवंशीय पशुओं का संरक्षण, आपदा से क्षतिग्रस्त विद्युत संरचनाओं के पुनर्स्थापन मानक, मेरठ-ऋषिकेश आरआरटीएस विस्तार, हरिद्वार-हर्रावाला रेल लाइन का दोहरीकरण, आपदा प्रभावित सिंचाई नहरों के पुनर्निर्माण मानक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय, आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु वन भूमि हस्तांतरण, वन संरक्षण अधिनियम में शिथिलीकरण तथा टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन परियोजना जैसे विषय शामिल रहे।

केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख विषय

बैठक में केंद्र सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पुल पुनर्निर्माण, खनिज विकास, मत्स्य पालन, पंचायती राज, कानून एवं न्याय, गृह, सहकारिता, महिला एवं बाल विकास, ऊर्जा, आवास, ग्रामीण विकास, रेल, पर्यावरण, जल जीवन मिशन और खाद्य सुरक्षा से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्य बैठक से पहले एजेंडा तय करने का अहम मंच

यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसमें मध्य क्षेत्रीय परिषद की मुख्य बैठक से पहले एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाता है। यहां लिए गए निर्णय और सिफारिशें परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाएंगी, जिससे अंतर्राज्यीय सहयोग, नीतिगत समन्वय और विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन को नई दिशा मिलेगी।

सूचना विभाग में दीर्घ सेवा देने वाले दो अधिकारियों को भावभीनी विदाई

पथ प्रवाह, देहरादून

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड के मुख्यालय में शनिवार को आयोजित गरिमामय सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में विभाग में शासकीय सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जगदीश सिंह पटवाल एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी दिनेश सिंह राणा को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सूचना कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने दोनों अधिकारियों के दीर्घ, समर्पित और अनुकरणीय सेवाकाल को स्मरण करते हुए उनके योगदान की सराहना की।

कार्यक्रम के दौरान अपर निदेशक सूचना आशिष कुमार त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक डॉ. नितिन उपाध्याय, उप निदेशक रवि विजारनिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारियों को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का वातावरण आत्मीयता, सम्मान और भावनाओं से परिपूर्ण रहा। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए अपर निदेशक सूचना आशिष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि किसी भी कार्मिक द्वारा 40 वर्ष और 34 वर्ष की दीर्घ शासकीय सेवा करना अपने आप में गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक अपने साथ कार्य अनुभव, अनुशासन और कार्य संस्कृति की अमूल्य धरोहर लेकर जाते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनती है। उन्होंने आपसी संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने पर बल देते हुए कहा कि मानवीय रिश्ते ही किसी भी संगठन की वास्तविक शक्ति होते हैं।

अपर निदेशक ने सुझाव दिया कि सूचना कर्मचारी संघ को भविष्य में सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए नियमित कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जिससे पुराने और नए कार्मिकों के बीच अनुभव और विचारों का सार्थक आदान-प्रदान हो सके। उन्होंने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जगदीश सिंह पटवाल एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी दिनेश सिंह राणा द्वारा विभाग की प्रगति में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान की मुक्त कंठ से सराहना की। संयुक्त निदेशक डॉ. नितिन उपाध्याय ने अपने संबोधन में कहा कि विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि विभाग की आज की उपलब्धियों में पूर्व एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है और उनका अनुभव विभाग की नींव को मजबूत करता है।

कार्यक्रम में फोटो फिल्म अधिकारी शेखर चन्द्र जोशी, सहायक लेखाकार कीर्ति सिंह पंवार एवं व्यवस्थाधिकारी रामपाल सिंह रावत ने भी अपने विचार साझा करते हुए सेवानिवृत्त अधिकारियों के कार्यकाल को अनुकरणीय बताया।

कार्यक्रम का संचालन प्रशासनिक अधिकारी विजय कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम में एल.पी. भट्ट सहायक निदेशक, मनोज कुमार शुक्ला मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सहायक लेखाकार राकेश कुमार धीमान, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रणजीत सिंह बुदियाल सहित सूचना कर्मचारी संघ के महामंत्री अंकित चैहान, उपाध्यक्ष प्रशांत रावत, संगठन मंत्री सत्येन्द्र विजल्वाण एवं अन्य पदाधिकारीगण, विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी उपस्थितजनों ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के स्वस्थ, सुखद एवं सक्रिय भविष्य की कामना की।

गुरु रविदास जयंती की पूर्वसंध्या पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रदेशवासियों के नाम संदेश

पथ प्रवाह, देहरादून

गुरु रविदास जयंती की पूर्वसंध्या पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन और शिक्षाओं को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी भारत के महान संतों में अग्रणी स्थान रखते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण मानव सेवा को समर्पित किया और समाज को समानता, एकता तथा भाईचारे का अमूल्य संदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपने संदेश में कहा कि संत रविदास जी ने अपनी वाणी और विचारों के माध्यम से जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करने की प्रेरणा दी। उन्होंने छुआछूत, सामाजिक असमानता और कुरीतियों के विरुद्ध निर्भीक होकर आवाज उठाई तथा प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन किया। उनकी शिक्षाएँ समाज को जोड़ने और मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ करने की आधारशिला हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्राप्त हों। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और सामाजिक चेतना का प्रतीक है। आज भी उनके विचार सामाजिक समरसता, सौहार्द और आपसी सद्भाव को मजबूत करने में अत्यंत प्रासंगिक और प्रेरणास्रोत हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे संत रविदास जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें और समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी द्वारा दिखाया गया मार्ग हमें सामाजिक बुराइयों, भेदभाव और कुरीतियों के विरुद्ध एकजुट होकर प्रयास करने की प्रेरणा देता है। अपने संदेश के अंत में मुख्यमंत्री ने कामना की कि संत रविदास जी की शिक्षाएँ सभी के जीवन में शांति, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें तथा उत्तराखण्ड निरंतर प्रगति, सामाजिक एकता और समरसता के पथ पर आगे बढ़ता रहे।

जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार: मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में जनसेवा का सशक्त मॉडल

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संचालित 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान राज्य में जनसेवा और सुशासन का एक सशक्त मॉडल बनकर सामने आया है। यह अभियान शासन और आम नागरिक के बीच सीधा संवाद स्थापित करते हुए जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जनता तक उनके निकट पहुँचाना है, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य के तहत प्रदेशभर में नियमित रूप से जनहितकारी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ विभिन्न विभागों की सेवाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज आयोजित किए गए 16 कैम्पों में 6,820 नागरिकों ने प्रत्यक्ष रूप से सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। यह आँकड़ा दर्शाता है कि राज्य सरकार की योजनाएँ अब केवल कागज़ों तक सीमित न रहकर ज़मीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू हो रही हैं। यदि अब तक की उपलब्धियों पर नजर डालें, तो प्रदेश में कुल 541 कैम्पों का सफल आयोजन किया जा चुका है। इन शिविरों के माध्यम से 4,28,183 नागरिकों तक विभिन्न सरकारी योजनाओं, सेवाओं और शिकायत निवारण की सुविधा पहुँचाई जा चुकी है। यह पहल मुख्यमंत्री धामी के उस विज़न को साकार करती है, जिसमें सरकार स्वयं जनता के द्वार तक पहुँचकर उनकी समस्याओं का समाधान करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएँ बनाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचे। 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान इसी सोच का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस अभियान से न केवल जनसमस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है, बल्कि शासन व्यवस्था में जनता की सहभागिता भी लगातार बढ़ रही है। पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशील प्रशासन की दिशा में यह अभियान उत्तराखण्ड में सुशासन की मजबूत नींव बन चुका है।

जल संरक्षण से सिंचाई हुई सुदृढ़, खेती को मिला संबल—कृषकों की आय में हुई वृद्धि

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा

जनपद अल्मोड़ा पर्वतीय एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र है। यहाँ सिंचाई व्यवस्था मुख्यतः सतही जल स्रोतों तथा वर्षा पर आधारित है। पर्वतीय ढालों, नालों एवं गधेरों में तेज बहाव के कारण वर्षा जल का अधिकांश भाग बहकर निकल जाता है, जिससे एक ओर भू-कटाव की समस्या बढ़ती है तो दूसरी ओर भूमिगत जल स्तर रिचार्ज नहीं हो पाता। परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित आजीविका प्रभावित होती है तथा पलायन जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं।

इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विकास खण्ड ताकुला के अंतर्गत ग्राम सारकोट में 24.13 लाख रुपए की लागत से जल संरक्षण एवं सिंचाई सुविधा को सुदृढ़ करने हेतु चैक डैम निर्माण योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया गया। यह योजना क्षेत्रीय कृषकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है और इसे जल एवं भूमि संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

अधिशाषी अभियंता लघु सिंचाई अल्मोड़ा जीडी सिंह ने अवगत कराया कि इस योजना से 16 परिवार सीधे रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। ये परिवार अपने खेतों में इस योजना से सिंचाई करके अपने कृषि कार्यों को बढ़ा रहे हैं।

योजना के सफल क्रियान्वयन से स्थानीय कृषकों को स्थायी सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई है। चैक डैम निर्माण ने न केवल खेतों तक पानी पहुँचाने में मदद की है, बल्कि जल संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन में भी एक प्रभावी मॉडल प्रस्तुत किया है।

समस्या की पृष्ठभूमि –

स्थानीय कृषकों की आय का प्रमुख साधन कृषि है, परंतु पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था न होने के कारण किसानों को अपनी फसल का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा था। विगत वर्षों में लगातार भू-कटाव होने से नालों एवं गधेरों का तल नीचे होता गया, जिससे गूलों में पानी का बहाव बाधित हो गया। इसके चलते खेतों तक समय पर पानी नहीं पहुँच पाता था और कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा था।

योजना निर्माण से पूर्व कृषकों द्वारा सिंचाई हेतु कच्चे बांध का उपयोग किया जाता था, लेकिन कच्चे बांध में रिसाव होने के कारण पर्याप्त पानी खेतों तक नहीं पहुँच पाता था। साथ ही, विगत वर्षों में आई आपदा एवं अतिवृष्टि के कारण जल स्रोत का हैड नीचे चला गया, जिससे सिंचाई के लिए जल उपलब्धता और भी कम हो गई। ऐसी स्थिति में किसान मजबूरी में वर्षा पर निर्भर हो गए थे।

चैक डैम निर्माण से बदली तस्वीर, समस्या का हुआ समाधान –

इन समस्याओं के समाधान हेतु ग्राम सारकोट में छोटे-छोटे चैक डैमों का निर्माण कराया गया। चैक डैम निर्माण का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल के बहाव को नियंत्रित कर जल संरक्षण, भूमि संरक्षण तथा भूमिगत जल रिचार्ज को बढ़ावा देना है। चैक डैमों से जल का संचय होने लगा, जिससे सामूहिक सिंचाई गूलों के माध्यम से खेतों तक पानी नियमित रूप से पहुँचने लगा।

योजना के निर्माण के उपरान्त चैक डैम से पर्याप्त मात्रा में पानी खेतों की सिंचाई हेतु उपलब्ध हो रहा है, जिसका लाभ कृषकों द्वारा पूर्ण रूप से लिया जा रहा है। इससे खेती की उत्पादकता बढ़ी है तथा किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक परिवर्तन आया है।

योजना से प्राप्त प्रमुख लाभ

चैक डैम निर्माण योजना से क्षेत्र में निम्नलिखित उल्लेखनीय लाभ सामने आए हैं–

7.7 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई सुनिश्चित हुई। 16 परिवार प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने से फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषकों की आय में बढ़ोतरी होने लगी है। जल संरक्षण एवं भूमि संरक्षण को बल मिला, जिससे भू-कटाव में कमी की संभावना बढ़ी। वर्षा पर निर्भरता कम होने से किसानों में आत्मविश्वास बढ़ा तथा कृषि कार्यों में निरंतरता बनी।

एक नजर

पुलिस लाइन में एनुअल स्पोर्ट्स डे, एसपी ने बच्चों का बढ़ाया हौसला

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी। पुलिस लाइन ज्ञानसू में आयोजित एमीज़ पब्लिक स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह में पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर स्कूली बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभा का प्रदर्शन किया, वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद और नियमित व्यायाम स्वस्थ जीवनशैली के लिए आवश्यक हैं। खेल न केवल शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होते हैं, बल्कि बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करते हैं। उन्होंने बच्चों से खेलों को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक जनक सिंह पंवार, प्रतिसार निरीक्षक शिव कुमार, स्कूल प्रबंधन एवं शिक्षकों के साथ अभिभावक भी मौजूद रहे। आयोजन के दौरान बच्चों की ऊर्जा, अनुशासन और खेल भावना ने दर्शकों को प्रभावित किया। कार्यक्रम का समापन उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ।

सुरक्षित बचपन की ओर कदम: बाल सुरक्षा व डिजिटल जागरूकता कार्यक्रम

पथ प्रवाह,पौड़ी। जिला परिवीक्षा अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी अरविंद कुमार के निर्देशन में जनता इंटर कॉलेज एवं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, ल्वाली में बाल सुरक्षा, बाल अधिकार एवं डिजिटल सुरक्षा विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को कानूनी अधिकारों, सुरक्षा तंत्र एवं सहायता सेवाओं के प्रति जागरूक कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं सजग बनाना रहा। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति की सदस्य सुनीता भट्ट ने पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों, शिकायत प्रक्रिया एवं पीड़ित बच्चों के संरक्षण से संबंधित जानकारी सरल भाषा में दी। प्रज्ञा नैथानी द्वारा मंच संचालन करते हुए 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन की 24म7 सेवा की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया। वहीं संरक्षण अधिकारी सागर लिंगवाल ने बच्चों को साइबर अपराधों, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग एवं ऑनलाइन सतर्कता के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य नागेंद्र प्रसाद जुगराण सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं, सामाजिक कार्यकर्ता सूरज कुमार एवं केस वर्कर धर्मेंद्र उपस्थित रहे।

विकास योजनाओं में सुस्ती पर डीएम नाराज, कम प्रगति वाले विभागों को फटकार

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रस्तावित जनपदवार समीक्षा बैठक की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जिला सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में 31 जनवरी 2026 तक जनपद में संचालित विकास योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ-साथ राजस्व प्राप्ति की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान जिला योजना, राज्य सेक्टर एवं केंद्र सरकार द्वारा बाह्यपोषित योजनाओं में अपेक्षित खर्च न होने और धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग समयबद्ध रूप से कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

बैठक में राजस्व, गृह विभाग सहित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, पर्यटन से संबंधित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना एवं होम-स्टे योजना, कृषि, उद्यान, पशुपालन, डेयरी और सहकारिता विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही कानून-व्यवस्था, आपराधिक मामलों, नशामुक्ति अभियान, कारागार से जुड़े प्रकरणों, अभियोजन कार्य एवं भूमि धोखाधड़ी मामलों पर भी चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए।

समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जय भारत सिंह, अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र, उपजिलाधिकारी भटवाड़ी शालिनी नेगी, उपजिलाधिकारी डुंडा देवानंद शर्मा, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी अतुल आनंद सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मां गंगा की स्वच्छता और उत्तरकाशी की रक्षा के लिए जारी जनसंघर्ष

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी।

जहां एक ओर नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी द्वारा वर्षों से लंबित 6 हजार मीट्रिक टन लिगेसी वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण को बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना आज 44वें दिन भी पूरी मजबूती और जनसमर्थन के साथ जारी है। यह आंदोलन मां गंगा की स्वच्छता, उत्तरकाशी की रक्षा और जवाबदेह प्रशासन की मांग को लेकर चलाया जा रहा है। इस जनआंदोलन का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता गोपीनाथ सिंह रावत ने नगर पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कागजों में किए जा रहे दावे और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका द्वारा 80 प्रतिशत कूड़ा उठाए जाने का दावा किया जा रहा है, जबकि मौके पर केवल लगभग 50 प्रतिशत कूड़ा ही हटाया गया है। वहीं नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी की ओर से आंदोलनकारियों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा गया कि शहर में कूड़ा निस्तारण को लेकर लगातार और गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि नगर क्षेत्र में वर्षों से जमा लगभग 6 हजार मीट्रिक टन लिगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा चुका है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

नगर पालिका के अनुसार पूर्व में कार्यरत फर्म द्वारा छोड़े गए तामखानी क्षेत्र के शेष पैच के निस्तारण के लिए री-टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और टेंडर स्वीकृति के बाद 20 दिनों के भीतर शेष कूड़े का निस्तारण कर लिया जाएगा। प्रशासन का दावा है कि तामखानी सुरंग क्षेत्र सहित शहर के अधिकांश हिस्सों से लगभग 80 प्रतिशत कूड़ा हटाया जा चुका है। नगर पालिका ने यह भी

स्पष्ट किया कि वर्तमान में कूड़े को केवल एकत्र नहीं किया जा रहा, बल्कि उसका वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल निस्तारण किया जा रहा है। गीले कूड़े से खाद तैयार की जा रही है, घरेलू सब्जी अवशेषों को गौशालाओं तक पहुंचाया जा रहा है तथा सूखे प्लास्टिक की छंटाई कर अवशिष्ट कचरे को आरडीएफ के रूप में फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि एमआरएफ (मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) सेंटर की स्थापना की प्रक्रिया भी प्रगति पर है, जिससे भविष्य में कूड़ा प्रबंधन और अधिक व्यवस्थित हो सकेगा। प्रशासन ने आंदोलनकारियों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और स्वच्छता अभियान में सहयोग करें, ताकि उत्तरकाशी को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल नगर के रूप में विकसित किया जा सके। आज धरना स्थल पर हिंदू संगठनों के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। हिंदू संगठन लगातार आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। इस दौरान दिनेश पंवार सहित पूरी टीम ने आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का संकल्प दोहराया। धरने से पूर्व सभी पदाधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे स्थित तामखानी रोड सुरंग के पास पड़े कूड़ा-कचरे का मौके पर मुआयना किया। मुआयने में यह साफ़ तौर पर सामने आया कि तामखानी सुरंग के बाहर अब भी भारी मात्रा में कूड़ा मौजूद है, जिसे प्रशासनिक दावों के विपरीत बताया जा रहा है। मौके के दृश्य वीडियो में भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। गोपीनाथ सिंह रावत ने कहा कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ नहीं, बल्कि झूठ, भ्रष्टाचार और षड्यंत्र के खिलाफ जनसंघर्ष है, जो तब तक जारी रहेगा जब तक उत्तरकाशी और मां गंगा की स्वच्छता को लेकर ठोस और पारदर्शी कार्रवाई नहीं होती।

मौके पर दिनेश पंवार, आचार्य गणेश चमोली, कीर्ति सिंह महर, रावल सतीश सेमवाल, राजपाल पवार, कुलबीर सिंह, धर्मेंद्र पवार, उमेश चौहान, मनोज कुमार, मथुरा प्रसाद, रमेश पवार, भगवान सिंह गोसाई, संतोष सेमवाल सहित अनेक सामाजिक एवं हिंदू संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

एक नजर

न्याय पंचायत हर्षू में बहुउद्देश्यीय शिविर का जनता ने उठाया लाभ

पथ प्रवाह, पौड़ी। जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के तहत विकासखंड दुगड्डा की न्याय पंचायत हर्षू में आयोजित किया गया। शिविर में 25 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं विभिन्न विभागीय योजनाओं के अंतर्गत 09 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। जबकि 02 लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु आवेदन पत्र भरे। नोडल अधिकारी/क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी लैंसडौन उत्तम कुमार ने विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। शिविर के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि शिविर में कृषि, समाज कल्याण, उद्यान, वन, स्वास्थ्य, आयुर्वेदिक एवं यूनानी, पशुपालन, खाद्य एवं पूर्ति, बाल विकास सहित कुल 23 विभागों ने सहभागिता कर अपने विभाग से संबंधित योजनाओं से स्थानीयों को लाभान्वित किया है। शिविर में कुल 25 शिकायतें दर्ज हुई, 09 पात्र लाभार्थियों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्या प्रमिला बलूनी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक रावत, पूर्व जिला पंचायत सदस्या मीरा रतूड़ी, एएई जल निगम वंदना, आयुष विभाग से डॉ बबीता कोहली सहित अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। नाबालिक लड़की को बहका फुसलकार अपहृत कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर अपहृता को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 27 जनवरी को वादी द्वारा लिखित तहरीर दी गई जिसमें वादी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना की गम्भीरता को देखते 31/1/2026 को मुकदमा उपरोक्त के नवीन पुत्र राजेश कुमार निवासी ग्राम सराय मिश्रन थाना खीरो जिला रायबरेली उ0प्र0 हाल पता रामधाम कालोनी थाना-सिडकुल जिला हरिद्वार को पकडा गया तथा मुकदमा उपरोक्त की पीड़िता सकुशल बरामद किया गया।

रिटायर हुए होमगार्ड जवान को दी शानदार विदायी

पथ प्रवाह, हरिद्वार। आमजन की सेवा के लिए हमेशा पुलिस के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले होमगार्ड व पीआरडी के जवानों का रिटायरमेंट अक्सर उनके जनपद मुख्यालय तक सिमट कर रह जाता है लेकिन रीत से अलग हटकर हरिद्वार पुलिस ने रिटायर हुए होमगार्ड जवान महिपाल सिंह को यादगार विदाई दी। आयोजित विदाई कार्यक्रम में थाना सिड़कुल पुलिस ने थाना प्रांगण में सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था कर सेवानिवृत्त हुए जवान व उनके परिजनों को आमंत्रित किया। इस दौरान कुछ खास पलों को संजोते हुए पूरे थाना स्टॉफ ने विगत 36 वर्षों से हर संघर्ष में साथ रहे होमगार्ड महिपाल सिंह को यादगार विदाई दी।

हॉकी प्रतियोगिता में हल्द्वानी ने अल्मोड़ा को और हरिद्वार ने पौड़ी को हराया

पथ प्रवाह, हरिद्वार। खेल निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून, जिला प्रशासन हरिद्वार के मार्गदर्शन एवं जिला खेल कार्यालय के तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में कड़े मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। अण्डर-18 प्रतियोगिता में उत्तराखण्ड राज्य के 11 जनपदों सहित 13 टीम प्रतिभाग कर रही हैं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन प्रतियोगिता का पहला मैच - जनपद हल्द्वानी एवं अल्मोडा के मध्य खेला गया जिसमें हल्द्वानी की टीम जनपद अल्मोडा को 6-0 से हराकर विजयी रही। प्रतियोगिता का दूसरा मैच - जनपद हरिद्वार एवं जनपद पौडी के मध्य खेला गया जिसमें जनपद हरिद्वार की टीम जनपद पौडी को 12-0 से हराकर विजयी रही। प्रतियोगिता का तीसरा मैच- जनपद नैनीताल एवं जनपद उधमसिंह नगर के मध्य खेला गया जिसमें दोनो जनपदो ने बराबर की टक्कर में 1-1 गोल बनाया। प्रतियोगिता का चौथा मैच - जनपद हरिद्वार (बी) एवं जनपद हल्द्वानी के मध्य खेला गया जिसमें जनपद हरिद्वार (बी) की टीम जनपद हल्द्वानी को 13-0 से हराकर विजयी रही। प्रतियोगिता का पाँचवा मैच - जनपद देहरादून एवं जनपद चम्पावत के मध्य खेला गया जिसमें जनपद दोनो टीम एक भी गोल बनाने असफल रही। प्रतियोगिता का छठवाँ मैच- जनपद हरिद्वार (बी) एवं जनपद नैनीताल के मध्य खेला गया जिसमें जनपद हरिद्वार (बी) की टीम ने नैनीताल को 8-0 को से हराकर विजयी रही। प्रतियोगिता का सातवाँ मैच- जनपद उधमसिंह नगर एवं जनपद पौडी के मध्य खेला गया जिसमें जनपद उधमसिंह नगर की टीम जनपद पौडी को 13-1 से हराकर विजयी रही। निर्णायको की भूमिका में अमित कटारिया, अमित नेगी, हरीश नेगी, महिमा भण्डारी, परमिता गौतम, सौरभ पटवाल रहे। इस अवसर पर शबाली गुरुंग जिला क्रीडा अधिकारी हरिद्वार, प्रजापति कुकरेती मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, विक्रम सिंह कनिष्ठ सहायक, शिखा बिष्ट, सहायक प्रशिक्षक, दीपक चन्द्र जोशी, सहायक प्रशिक्षक, गौरव लौहान, मंगल सिंह, शुभम बोहरा, अभिषेक मुरारी, अनुराग सिंह धमान्दा, एंव अनेक खेलप्रेमी उपस्थित रहे।

मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहा था नशे का कारोबार, एक आरोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह, कुमाऊँ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 'ड्रग्स फ्री उत्तराखण्ड' अभियान के तहत नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में कुमाऊँ पुलिस की एसओटीएफ टीम एवं औषधि विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी सफलता हासिल करते हुए अवैध नशीली दवाओं की भारी बरामदगी की है।

पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊँ परिक्षेत्र श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल तथा स्वास्थ्य सचिव के निर्देशन में कल सायं 30 जनवरी 2026 को एसओटीएफ कुमाऊँ परिक्षेत्र और औषधि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थाना किच्छा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़िया स्थित मेडिकल स्टोर्स की सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्राम बड़िया रोड पर स्थित 'संतोष मेडिकल स्टोर' की तलाशी ली गई।

मेडिकल स्टोर के अंदर बने रैकों की जांच के दौरान संदिग्ध एवं प्रतिबंधित दवाइयाँ पाई गईं। मौके पर मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम संतोष कुमार पुत्र हेमराज, निवासी छिनकी दरऊ, किच्छा, जिला ऊधमसिंहनगर, उम्र 26 वर्ष बताया। तलाशी में कुल 270 पत्ते (2160 कैप्सूल) अवैध नशीली दवाइयाँ बरामद की गईं।

पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कोतवाली किच्छा में धारा 08/22 एनडीपीएस एक्ट, 1985 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। इस संयुक्त कार्रवाई में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक शुभम कोटनाला, एसओटीएफ कुमाऊँ परिक्षेत्र टीम तथा कोतवाली किच्छा पुलिस के उपनिरीक्षक दीपक जोशी एवं हेड कांस्टेबल कुलदीप शामिल रहे।

पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊँ परिक्षेत्र ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि नशे के अवैध कारोबार के प्रति कुमाऊँ परिक्षेत्र में ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी।

सूगी करछूना की छात्रा का एनएमएमएस परीक्षा में चयन

पथ प्रवाह, पोखरी/चमोली

राजकीय जूनियर हाई स्कूल सूगी करछूना की कक्षा 8 की छात्रा कुमारी प्रिया नेगी ने राष्ट्रीय साधन सह मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा (हस्स्स्) में चयनित होकर विद्यालय, क्षेत्र एवं अपने परिवार का नाम रोशन किया है। उल्लेखनीय है कि विद्यालय से विगत कई वर्षों से छात्र-छात्राएं इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता प्राप्त करते आ रहे हैं। यह उपलब्धि विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था, अनुशासित शैक्षणिक वातावरण तथा शिक्षकों के सतत मार्गदर्शन का प्रमाण है। छात्रा की इस सफलता पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक वेद प्रकाश भट्ट सहित गाइड शिक्षक कल्याण सिंह चौधरी, विनोद पुरोहित एवं जगजीवन सिंह कनवासी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कुमारी प्रिया नेगी को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर एसएमसी अध्यक्ष विनोद कोहली, ग्राम प्रधान विमला बुटोला, विक्रम नेगी एवं संतोष सिंह ने भी विद्यालय की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर बधाई संदेश प्रेषित कर हर्ष व्यक्त किया। विद्यालय परिवार ने छात्रा की इस सफलता को अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बताते हुए कहा कि परिश्रम, अनुशासन और सही मार्गदर्शन से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं।

ऑपरेशन कालनेमी: अलग-अलग थानों की कार्यवाही में 48 कालनेमियों को पकड़ा

पथ प्रवाह, हरिद्वार। मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के निर्देशित क्रम में पूरे राज्य में चलाए जा रहे आपरेशन कालनेमि के तहत हरिद्वार पुलिस द्वारा चैकिंग अभियान चलाकर धर्म की आड़ में धोखाधड़ी करने वाले, बिना पहचान पत्र के रहने वाले अलग- अलग थानों द्वारा 48 ढोगी बाबाओं के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उन्हे हिरासत में लिया गया। बाबाओं के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कोतवाली नगर हरिद्वार पुलिस द्वारा कुल 28 ढोंगी बाबाओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई। कोतवाली रानीपुर पुलिस द्वारा कुल 11 ढ़ोंगी बाबाओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई। थाना बहादराबाद पुलिस द्वारा 09 ढ़ोंगी बाबाओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई। हरिद्वार पुलिस का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। सभी थाना क्षेत्रों में प्रमुखता से यह अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रवासी उत्तराखण्डियों से संवाद का सशक्त मंच बना 'उत्तराखण्ड महोत्सव रोहिणी-02'

पथ प्रवाह, नई दिल्ली/रोहिणी।

दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में 'हम सबका उत्तराखण्ड' संस्था द्वारा आयोजित 'उत्तराखण्ड महोत्सव रोहिणी-सीजन 02' प्रवासी उत्तराखण्डियों के लिए संवाद, संस्कृति और आत्मीय जुड़ाव का सशक्त मंच बनकर उभरा। इस भव्य सांस्कृतिक आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहभागिता करते हुए उत्तराखण्ड की लोकसंस्कृति, परंपराओं और विरासत को जीवंत बनाए रखने के प्रयासों की सराहना की।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखण्डी, लोक कलाकार, युवा और महिलाएं उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लोक कलाकारों से संवाद किया, उनके प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन न केवल कलाकारों को मंच और सम्मान देते हैं, बल्कि समाज को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का भी कार्य करते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 'उत्तराखण्ड के सितारे' सम्मान से सुप्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सौरभ जोशी, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मनोज गोरखेला तथा लोक गायिका कल्पना चौहान को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सम्मानित व्यक्तित्वों के योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये सभी अपने-अपने क्षेत्रों में उत्तराखण्ड का नाम देश और दुनिया में रोशन कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति आज भी अपने गीतों, नृत्यों, वेशभूषा और परंपराओं के माध्यम से जीवंत है। देश-विदेश में निवास करने वाले उत्तराखण्डी अपनी सांस्कृतिक पहचान से गहराई से जुड़े हुए हैं और ऐसे आयोजन इस भावनात्मक संबंध को और सशक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक लोकगीत और लोकनृत्य राज्य की सांस्कृतिक चेतना के संवाहक हैं।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे बच्चों और युवाओं में अपनी बोली, संस्कृति और परंपराओं के प्रति गर्व की भावना विकसित होती है। लोक संस्कृति के संरक्षण से सामाजिक एकता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास को मजबूती मिलती है।

मुख्यमंत्री ने देवभूमि उत्तराखण्ड को आस्था, तप, त्याग और साधना की भूमि बताते हुए कहा कि बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगा-यमुना और आदि कैलाश जैसे पवित्र स्थलों के कारण उत्तराखण्ड को वैश्विक पहचान प्राप्त है। उन्होंने कहा कि स्वयं पहाड़ से जुड़े होने के कारण लोकसंस्कृति उनकी जीवनशैली और संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रही है, इसी सोच के साथ राज्य सरकार संस्कृति को विकास से जोड़कर आगे बढ़ रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकास भी और विरासत भी' मंत्र का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी दृष्टिकोण के तहत राज्य में धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों का पुनर्विकास किया जा रहा है। केदारनाथ और बदरीनाथ धाम के पुनर्निर्माण से आस्था के साथ-साथ पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी नई दिशा मिली है। मंदिर माला मिशन के माध्यम से धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड आज वेडिंग डेस्टिनेशन, एडवेंचर टूरिज्म और फिल्म शूटिंग के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। विंटर टूरिज्म, 'वेड इन उत्तराखण्ड' और होम-स्टे जैसी पहलों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। कृषि, दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर ग्रामीण आजीविका को सशक्त किया जा रहा है।

महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं। 'एक जनपद-दो उत्पाद' योजना और 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड से राज्य के उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता की उन्होंने विशेष रूप से सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद उत्तराखण्ड ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य की अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय, बजट, बिजली उत्पादन और स्वास्थ्य सुविधाओं में निरंतर सुधार हुआ है। पलायन रोकने, किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

उन्होंने कहा कि सख्त कानूनों, पारदर्शी शासन और समान नागरिक संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तराखण्ड में सुशासन को मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित 'उत्तराखण्ड का दशक' को साकार करने के लिए राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कलाकार तथा विभिन्न क्षेत्रों से आए गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

पतंजलि और सिक्किम सरकार के संयुक्त प्रयास में बहुत संभावनाएं: स्वामी रामदेव

योग से मन, शरीर और आत्मा में होता है संतुलन स्थापित : आचार्य बालकृष्ण

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

पतंजलि अनुसंधान संस्थान एवं वेलनेस, हरिद्वार में 'योगा ओलंपियाड ओरिएंटेशन एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम' का नौ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का पतंजलि अनुसंधान संस्थान एवं वेलनेस में संपन्न हुआ। 22 से 30 जनवरी तक चला प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा। यह कार्यक्रम योगदर्शन, मनोविज्ञान एवं आध्यात्मिकता पर आधारित था, जो आंतरिक शांति एवं आध्यात्मिक चिंतन की दिशा प्रदान करता है।

इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग सिक्किम सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, समानता एवं योग के व्यापक प्रसार को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मेडिटेशन, शंख वादन और हवन पूजन से हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि योग प्राचीन भारत की एक समग्र शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक साधना है। योग का उद्देश्य मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना है, जिससे आत्म-साक्षात्कार, मानसिक शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। योग के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है, तनाव कम होता है तथा अनुशासित जीवनशैली अपनाने में सहायता मिलती है।

इस अवसर पर योगऋषि स्वामी रामदेव ने कहा कि नेचुरोपैथी अर्थात प्राकृतिक चिकित्सा एक औषधि-रहित उपचार पद्धति है, जो शरीर की स्वाभाविक उपचार क्षमता को सक्रिय करती है। इसमें संतुलित आहार, जड़ी-बूटियाँ, जल एवं मिट्टी चिकित्सा, योग, प्राणायाम, उपवास, सूर्य चिकित्सा एवं एक्यूपंक्चर के माध्यम से रोगों के मूल कारणों का उपचार किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा एक प्रभावी पूरक उपचार पद्धति है, लेकिन गंभीर रोगों में अनुभवी चिकित्सक की सलाह अत्यंत आवश्यक होती है। साथ ही उन्होंने पतंजलि एवं सिक्किम सरकार के संयुक्त प्रयासों की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला।

पतंजलि वेलनेस के संदर्भ में डॉ. विनिता ने बताया कि आयुर्वेद एवं प्राकृतिक जीवनशैली अपनाकर ही शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखा जा सकता है। उपचार की विधि रोग की प्रकृति, रोगी की स्थिति एवं विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर निर्धारित की जाती है।

कार्यक्रम के दौरान डॉ. वेदप्रिया आर्या ने पतंजलि की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का विस्तृत परिचय प्रस्तुत किया। इस अवसर पर डॉ. विशाल, सौरभ निर्मोही, डॉ. दीपिका, डॉ. विनिता सहित अन्य पतंजलि वैज्ञानिकों की सक्रिय सहभागिता रही।

प्रतिनिधियों ने ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन, गीता भवन तथा गंगा आरती में भी सहभागिता कर आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव किया। सिक्किम से आए प्रतिनिधियों ने पतंजलि गौशाला, गुरुकुलम्, आचार्यकुलम्, हर्बल गार्डन एवं अनुसंधान केंद्र का भ्रमण कर पतंजलि द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

कार्यक्रम में प्रमुख प्रतिनिधियों के रूप में अधिकारी एवं जामयांग भूटिया उपस्थित रहे। समापन अवसर पर आचार्य बालकृष्ण ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें प्रतीक-चिह्न एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने अतिथियों का शाल और स्मृति चिंह् देकर स्वागत किया। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने आगंतुकों का शाल एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर स्वागत किया।

शरदीय कांवड मेला की तैयारी, बार्डर मीटिंग में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुआ मंथन

पथ प्रवाह, हरिद्वार। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के निर्देश पर आगामी शरदीय कांवड मेला/महाशिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत शनिवार को होटल पिनाका, थाना श्यामपुर में बार्डर मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में एसपी सिटी हरिद्वार, सीओ सिटी हरिद्वार, ट्रैफिक इंस्पेक्टर हरिद्वार, एसओ श्यामपुर व जनपद बिजनौर से एसपी सिटी, सीओ नजीबावाद, एसएचओ मण्डावली द्वारा प्रतिभाग किया गया। गोष्टी में 2 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होने वाले शरदीय कांवड मेला और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व के परिपेक्ष्य में कांवड यात्रा के सकुशल सम्पन्न कराये जाने के लिए मंथन किया गया। उपस्थित अधिकारियो द्वारा आपसी समन्वय गोष्टी आयोजित कर कांवडियों/श्रद्धालुओ का सुरक्षित आवगमन सुनिश्चित कराये जाने पर चर्चा की। इस दौरान सूचनाओं का आदान प्रदान कर यातायात प्लान को शेयर किया गया। बार्डर पर प्रभावी चैकिंग हेतु पुलिस प्रबन्धन किये जाने पर चर्चा कर पर्याप्त पुलिस बल नियुक्त किया जाना निर्धारित किया गया।

वैश्विक झंझावातों के बीच बजट में विकास और राजकोषीय अनुशासन में संतुलन बिठाने की चुनौती

नयी दिल्ली। बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच रविवार को पेश किये जाने वाले आम बजट 2026-27 में सरकार के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक वृद्धि की गति और विकास की प्राथमिकताओं, राजकोषीय अनुशासन और जरूरतमंदों के रोजगार तथा कल्याण को सुरक्षित रखने के बीच संतुलन बिठाने की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 01 फरवरी को लोकसभा में अपना लगातार नौवां बजट पेश करेंगी। विश्लेषकों के अनुसार, इस बजट में निवेशकों और करदाताओं को किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद नहीं लगती, पर वित्त मंत्री आम लोगों के लिए कुछ नयी पहलें कर बजट को उनके लिए आकर्षक बनाने की कोशिश कर सकती हैं। यह बजट आठवें वेतन आयोग और 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रभावी होने के पहले वर्ष के लिए होगा। इसके मद्देनजर सरकार को विशेष रूप से राजकोषीय समायोजन करने पड़ सकते हैं। आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट अभी नहीं आयी है, लेकिन इसे 01 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा की जगह लाये गये 'विकसित भारत जी राम जी' योजना के लिए बजट पर लोगों का विशेष ध्यान होगा क्योंकि संशोधित नया कानून लागू होने का यह पहला बजट होने जा रहा है।

कोविड के बाद राष्ट्रीय खजाने के घाटे को सीमित करने का सराहनीय काम करने के साथ-साथ बचत और पूंजीगत व्यय के प्रोत्साहन के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज करने वाली श्रीमती सीतारमण के सामने अब चुनौती विकसित भारत-2047 की वृहद योजना के लिए उनके पिछले दो-तीन बजटों में की गयी बुनियादी पहलों के लिए धन के प्रबंध के साथ साथ वैश्विक चुनौतियों के नकारात्मक प्रभावों से घरेलू अर्थव्यवस्था को संभालना है।

राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के मद्देनजर रक्षा क्षेत्र में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना एक बड़ी आवश्यकता बन गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में जीवन और कारोबार को करने के लिए सुधारों को आगे बढ़ने का आश्वसान देते हुए कहा है कि देश इस समय 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पर है। इसलिए, बजट में सुधारों को बढ़ने तथा परमाणु ऊर्जा जैसे निजी निवेश के लिए खोले गये नये क्षेत्रों के लिए बजट में किये जाने वाले प्रावधानों पर लोगों की निगाह रहेगी। सरकार भारत को लगातार विनिर्माण क्षेत्र के एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रोत्साहित करने में लगी हुई है।

स्वामी/प्रकाशक वीरेन्द्र सिंह ने मुद्रक प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कराकर, मुख्य कार्यालयः 40 शांतिपुरम कॉलोनी जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड 249408 (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया। वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) 9411111733, डॉ सुशील शर्मा(उप संपादक) 9837906777 किसी भी वाद विवाद का निपटारा हरिद्वार में होगा। वेबसाईट- www.pathpravah.com